



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
दिशा निर्देश – 2025

ग्रामीण विकास विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-6)

☎ 0141-2227052

✉ pdsap-rd-rj@gov.in

Website: rdprd.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ.55(01)ग्रावि/SAP/CM-Thar-BADP/मार्गदर्शिका/2025-12932 जयपुर, दिनांक : 26.03.2025

:: मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम – दिशा निर्देश ::

1. प्रस्तावना :-

राजस्थान प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्र जो सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों के कारण यह क्षेत्र आधारभूत ढांचा आर्थिक एवं सामाजिक विकास से वंचित रह जाता है। अतः इन क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं हेतु आवश्यक विशेष विकास और उनके रहन-सहन से जुड़े हुए आवश्यक मूलभूत ढांचागत विकास यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि तथा पेयजल के उन्नयन हेतु राजस्थान सरकार के बजट घोषणा 2025-26 के बिन्दु संख्या 23 के अंतर्गत की गई घोषणा के अनुसरण में “मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम” प्रारंभ किया जा रहा है।

2. कार्यक्रम का नाम :-

कार्यक्रम का नाम “मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम” होगा।

3. कार्यक्रम का उद्देश्य :-

यह कार्यक्रम राजस्थान प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन हेतु चयनित क्षेत्र में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं प्रदेश के विकास के लिए भौगोलिक-आर्थिक-सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय भिन्नताओं, समस्याओं, आवश्यकताओं एवं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर करते हुए समग्र विकास पर बल देगा।

(Handwritten signature)

4. कार्यक्रम का क्षेत्र :-

यह कार्यक्रम, राजस्थान प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य के चयनित आबाद गांवों/कस्बों/अर्धशहरी/शहरी क्षेत्रों में संचालित होगा। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सभी पहली आबादियों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, इस कार्यक्रम के लिए शून्य रेखा होगी।
उक्त योजना अन्तर्गत चिन्हित आबाद गांवों का विवरण निम्नानुसार हैं -

क्र.सं.	जिलें का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्रामों की संख्या	जनसंख्या (2011 जनगणना अनुसार)
1.	बाड़मेर	चौहटन	28	26160
		धनाऊ	16	30661
		फगलिया	18	29039
		गडरा रोड़	58	41254
		रामसर	47	26642
		सेड़वा	16	22742
		योग	183	176498
2.	बीकानेर	खाजूवाला	30	40936
		बज्जू खालसा	7	4238
		योग	37	45174
3.	जैसलमेर	मोहनगढ़	6	7622
		नाचना	27	10292
		सम	111	19248
		योग	144	37162
4.	श्री गंगानगर	अनुपगढ़	199	62862
		घड़साना	167	43510
		करणपुर	151	178934
		पदमपुर	36	15949
		रायसिंहनगर	134	51792
		श्री गंगानगर	108	90740
		विजयनगर	47	14414
		योग	842	458201
महायोग			1206	717035

5. कार्यक्रम की विशेषताएं :-

1. यह शत प्रतिशत राज्य वित्त पोषित कार्यक्रम है।
2. यह कार्यक्रम क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निस्तारण पर बल देगा।

8/11

3. केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के साथ ही स्थानीय निकायों की व्यक्तिगत/स्टेण्ड अलोन परियोजनाओं के साथ अभिसरण किया जा सकेगा, बशर्ते ऐसे कार्य कार्यक्रम अन्तर्गत अनुमत हों।
4. कार्यक्रम अन्तर्गत आधारभूत ढांचा, आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं से संबंधित गतिविधियों पर बल दिया जायेगा।
5. इस कार्यक्रम द्वारा ऐसे कार्यों पर ही राशि व्यय की जा सकेगी, जिससे सृजित होने वाली परिसम्पत्तियां किसी राजकीय विभाग/शहरी निकाय/पंचायती राज संस्था के स्वामित्व की हों।
6. कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) एवं राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग (अनुभाग-6) प्रशासनिक विभाग होगा।

6. कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :-

कार्यक्रम अन्तर्गत गांव के समग्र विकास हेतु मूल आधारभूत सुविधाओं एवं क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु निम्नानुसार शामिल विभिन्न गतिविधियों के कार्य प्राथमिकता से करवाये जायेंगे -

- **शिक्षा एवं स्वास्थ्य (Education and Health) :-** चयनित क्षेत्रों में छात्र संख्या के अनुपात में शाला भवनों एवं कमरों का निर्माण, आंगनबाड़ी भवन, ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम की स्थापना, जीर्ण पड़े भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार, छात्रावासों का निर्माण, पुराने छात्रावासों की मरम्मत एवं उनका जीर्णोद्धार व चारदीवारी का निर्माण इत्यादि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इकाईयों के भवनों का निर्माण, चिकित्सीय उपकरण/मशीन, शिक्षा एवं चिकित्सा केन्द्रों में शौचालय एवं पेयजल/आरओ, वाटरकूलर की सुविधा, छात्रों के शारीरिक एवं कौशल विकास हेतु खेल मैदान एवं पुस्तकालय हेतु भवनों का निर्माण।
- **पेयजल (Drinking Water) :-** प्रत्येक गांव में वर्ष-पर्यन्त स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, प्रत्येक राजकीय/सामुदायिक परिसर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता। फ्लोराईड युक्त पानी, खारा पानी वाले क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेन्ट/आरओ प्लांट।

- **सम्पर्क सड़क (Connecting Roads) :-** प्रत्येक गांव में सुगम यातायात हेतु आन्तरिक सड़कों एवं नाली, राजकीय कार्यालय, शिक्षा एवं चिकित्सा केन्द्रों हेतु सुगम पहुँच मार्ग, प्रत्येक गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ना एवं पुल/पुलिया निर्माण कार्य।
- **ऊर्जा (Energy) :-** राजकीय भवनों, शिक्षा एवं चिकित्सा केन्द्रों में सौर प्लांट कार्य अनुमत होंगे किन्तु आवर्ती व्यय अनुमत नहीं होंगे। गांवों के आम रास्तों, सार्वजनिक स्थलों एवं ग्राम चौपालों पर रोशनी की व्यवस्था।
- **कृषि एवं पशुपालन अवसंरचना (Agriculture & Animal Husbandry Infrastructure) :-** लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण एवं जल संरक्षण संबंधित कार्य, पशु चारा संग्रहण केन्द्रों का निर्माण, पशुओं के पीने के लिए खेली आदि निर्माण।
- **खेल अवसंरचना (Sports Infrastructure) :-** खेल मैदानों का निर्माण/विकास, खेल स्टेडियम का निर्माण, Open Gym/ शारीरिक फिटनेस उपकरणों की स्थापना।
- **पर्यटन एवं संस्कृति (Tourism & Culture) :-** पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का विकास जिसमें पुरातत्व एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का विकास एवं संरक्षण, शौचालय, पेयजल, रोशनी, सामुदायिक भवन, संपर्क सड़क व पार्किंग आदि सुविधाओं का विकास शामिल हैं।
- **महिला सशक्तीकरण (Women Empowerment) :-** स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों की बिक्री में सहयोग, बाजार उपलब्धता, हाट निर्माण, राजीविका अन्तर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रशिक्षण, उत्पादों के वितरण आदि के लिए संकुल स्तरीय संगठन के लिए कार्यशाला भवन का निर्माण एवं महिलाओं के आजीविका संवर्धन के कार्य।
- **कौशल विकास (Skill Development) :-** चयनित क्षेत्र से ग्रामीणों के पलायन रोकने, स्थानीय निवासीयों के आजीविका संवर्धन हेतु ब्लॉक स्तर पर कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना जा सकेगी। इन केन्द्रों हेतु आवृत्ति व्यय अनुमत नहीं होगा।
चयनित क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के अन्य आवश्यक कार्य राज्य स्तर से सक्षम स्वीकृति लेते हुए कराये जा सकेंगे।

7. गैर अनुमत कार्य :-

1. निजी संस्थाओं हेतु परिसम्पत्तियों का निर्माण।
2. किसी भी पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट को स्वयं की परिसम्पत्तियां बनाने के लिए राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी। लेकिन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से संबद्ध संस्थाओं हेतु कार्य योजनान्तर्गत करवाये जा सकेंगे।
3. धार्मिक स्थल, समाज/जाति विशेष हेतु कार्य।
4. भूमि अधिग्रहण मुआवजा/सब्सिडी।
5. गैर सरकारी संस्थाओं हेतु परिसम्पत्तियों का निर्माण।
6. अन्य योजनाओं में स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाया जाना।
7. व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का निर्माण।
8. अनुदान, ऋण।
9. सजावट, सौन्दर्यीकरण एवं अस्थाई प्रकृति के कार्य।
10. केवल वस्तु एवं सामान का क्रय।
11. आपदा प्रबन्धन हेतु सहायता के कार्य।
12. कार्यालय भवन निर्माण एवं वाहन क्रय।
13. अपने नियंत्रण के अधीन के या सरकार या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा उसे अन्तरित भवनों का रखरखाव।
14. राजकीय आवास परिसर का निर्माण।
15. आवर्ती व्यय, जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार पर व्यय अनुमत नहीं होगा।

8. कार्यक्रम का कार्यान्वयन :-

1. वार्षिक कार्ययोजना -

- i. कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तर पर क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत ढांचागत विकास के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में जिले को आवंटित राशि के अनुरूप सम्मिलित कार्यों का प्राथमिकता के क्रम में जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन उपरांत विभागीय ई-वर्क पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा।
- ii. वार्षिक कार्य योजना में किसी भी कार्य की न्यूनतम धनराशि सामान्य रूप से 5 लाख रुपये से कम नहीं होगी तथापि यदि जिला स्तरीय समिति का यह

सुविचारित विचार है कि कम राशि का कार्य व्यापक रूप से जनता के लिए लाभकारी होगा तो ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से दर्ज किये जाने वाले कारणों को अभिलिखित करते हुए कार्ययोजना में ऐसे कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है।

- iii. जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला विकास वार्षिक योजना के अनुमोदन से पूर्व वार्षिक योजना में शामिल कार्यों के तकमीनों (Estimates) की व्यवहारिकता एवं तकनीकी परीक्षण सुनिश्चित कर लिया जावे।
- iv. जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित जिला विकास वार्षिक योजना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा विभागीय ई-वर्क पोर्टल पर इन्द्राज किया जायेगा।
- v. वार्षिक कार्ययोजना में राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन उपरांत यदि कोई भी परिवर्तन/संशोधन प्रस्तावित हो तो, राज्य सरकार के स्तर से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

2. स्वीकृति एवं निष्पादन –

- i. राज्य स्तर से अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार कार्यों की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा विभागीय ई-वर्क पोर्टल के माध्यम से प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका एवं विभागीय निर्देशों के अनुसार जारी की जायेगी।
- ii. कार्य स्वीकृति से पहले स्वीकृतकर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कार्यों के लिए सभी वैधानिक एवं नियामक मंजूरी सक्षम प्राधिकरणों से प्राप्त कर ली गयी हैं, एवं कार्य इन दिशा निर्देशों के अनुरूप है।
- iii. कार्यान्वयन एजेंसियां कार्यों को निष्पादित करते समय निर्धारित प्रक्रियाओं एवं प्रणाली का अक्षरशः पालन करेगी।
- iv. यदि किसी कारणवश किसी कार्य को रोकना/छोड़ना अपरिहार्य हो जाता है तो प्रकरण को पूर्ण औचित्य एवं उत्तरदायी कार्मिकों के उल्लेख के साथ राज्य सरकार को निर्णयार्थ प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

- v. सामान्यतया: निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन केन्द्र/राज्य सरकार के राजकीय विभाग/स्वायत्तशासी निकाय/पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से करवाया जाएगा, किन्तु आवश्यकता अनुसार कोई कार्य राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा विशेष विधि के तहत गठित निगम/बोर्ड/अभिकरण जो कार्य करने में सक्षम हैं, के माध्यम से करवाया जा सकेगा। कार्यों हेतु कार्यकारी संस्था को प्रोरेटा चार्ज देय नहीं होगा।
- vi. कार्यों के क्रियान्वयन/निरीक्षण के संबंध में विभाग द्वारा जारी प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की व्यवस्थाएं लागू होगी।
- vii. योजनान्तर्गत राजकीय विभागों/बोर्ड/निकाय हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कार्य संबंधित विभाग/एजेन्सी की प्रचलित बीएसआर दरों से तकमीने तैयार करवाये जायेंगे तथा उनका क्रियान्वयन भी तदनुसार कराया जा सकेगा, परन्तु कार्य पर कोई प्रोरेटा चार्ज देय नहीं होगा।
- viii. कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी प्रचलित कार्य निर्देशिका के अनुरूप तैयार करवाये जायेंगे।
- ix. अभिलेख संधारण विभाग द्वारा जारी प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तैयार करवाये जायेंगे।

3. निगरानी एवं अंकेक्षण :-

i. ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका -

1. राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं राज्य स्तर पर संरक्षित राशि हेतु अनुमोदित प्रस्तावों को विभागीय ई-वर्क पोर्टल पर स्वीकृति हेतु संबंधित जिलों को अग्रेषित करना।
2. योजना में जारी निधियों की समग्र स्थिति, स्वीकृत कार्यों की प्रगति, उपयोग की गई निधि आदि सहित योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जिलों से समन्वय स्थापित करते हुए नियमित समीक्षा करना।

3. समय-समय पर विभागीय ई-वर्क पोर्टल के माध्यम से योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेगा और कार्यों के समय पर निष्पादन के लिए समय-समय पर जिलों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करना।
4. कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु लाइन विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
5. कार्यक्रम अन्तर्गत वित्त विभाग से समन्वय कर जिलों को निधियां जारी करना।
6. कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु आकस्मिक निरीक्षण करना।
7. कार्यक्रम के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में आवश्यक संशोधन एवं अन्य आवश्यक निर्देश जारी करना।

ii. जिला प्राधिकारियों की भूमिका –

1. जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के प्रस्तावों को विभागीय ई-वर्क पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तर को प्रेषित करना।
2. अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना/प्रस्तावों के अनुसार कार्यों की स्वीकृति विभागीय ई-वर्क पोर्टल के माध्यम से जारी करना।
3. जिला स्तर पर योजना के तहत कार्यों की समग्र निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी।
4. कार्यक्रम के तहत करवाये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता के मापदण्ड, प्रचलित दिशा-निर्देश एवं प्रावधानों की पालना हेतु उत्तरदायी।
5. कार्यक्रम के तहत करवाये जाने वाले कार्यों के नियमित निरीक्षण हेतु उत्तरदायी।
6. जिला स्तर पर प्रत्येक माह में कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
7. कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्ण किए गए और प्रगतिरत कार्यों में से प्रतिदर्श (Sample) कार्यों का स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन करवाना।

8. कार्यक्रम में हुए व्यय की प्रति वर्ष सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण करवाया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर विभाग को भिजवाया जाएगा।
9. विभाग के ई-वर्क पोर्टल पर कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति का नियमित इन्द्राज करना।
10. प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्यों को पूर्ण कराना, समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार शास्ति/अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
11. किसी भी संबंधित व्यक्ति/संस्था द्वारा योजना दिशा-निर्देश के उल्लंघन, लापरवाही, भ्रष्टाचार आदि की स्थिति में जिम्मेदारी निर्धारित कर नियमानुसार अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्यवाही करना।

iii. कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका –

1. विस्तृत तकमीना अनुसार निर्धारित तकनीकी मापदण्डों की पालना करते हुए कार्यों का गुणवत्ता पूर्ण सम्पादन करवाना।
2. कार्यों को गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करवाना।
3. कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कार्य स्थलों का नियमित रूप से दौरा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया, विनिर्देशों और समय सीमा अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है।
4. कार्य पूर्ण होने पर कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा मूल्यांकन उपरांत प्रेषित करना।

9. वित्तीय प्रावधान :-

1. यह कार्यक्रम पूर्णतया राज्य वित्त पोषित योजना होगी।
2. कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट प्रावधान पृथक से किया जायेगा।
3. कार्यक्रम अन्तर्गत आवंटित राशि का विभाजन निम्नानुसार किया जायेगा –
 - i. 80 प्रतिशत राशि जिलों को वार्षिक कार्ययोजना हेतु आवंटित की जायेगी।

- ii. 19 प्रतिशत राशि राज्य स्तर पर संरक्षित रहेगी, जिसका व्यय राज्य स्तर के निर्देशानुसार किया जायेगा।
- iii. 01 प्रतिशत राशि प्रशासनिक मद हेतु उपलब्ध होगी।
4. वार्षिक कार्ययोजना हेतु जिलों को निम्नांकित मापदण्डों के अनुसार राशि आवंटित की जाएगी –
 - i. जिलों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई – 34 प्रतिशत अधिमान।
 - ii. जिलों में चयनित क्षेत्र का क्षेत्रफल – 33 प्रतिशत अधिमान।
 - iii. जिले में चयनित क्षेत्र की आबादी – 33 प्रतिशत अधिमान।
5. इस कार्यक्रम में उपलब्ध निधि में से 01 प्रतिशत निधि प्रशासनिक व्यय हेतु उपलब्ध होगी, जिसका आवंटन निम्नानुसार किया जाएगा –
 - i. राज्य स्तर हेतु – कुल आवंटन का 0.34 प्रतिशत।
 - ii. जिला स्तर हेतु – कुल आवंटन का 0.66 प्रतिशत (प्रत्येक जिले को समान अनुपात में)।

10. बजट आवंटन प्रक्रिया –

1. राज्य स्तर से संबंधित जिले को बिन्दु संख्या 9.4 के अनुसार वित्त वर्ष के प्रथम माह में राशि आवंटित की जायेगी।
2. आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ववर्ती वर्ष/वर्षों की वचनबद्ध देयताओं के लिये समुचित राशि को आरक्षित रखते हुए शेष उपलब्ध राशि के विरुद्ध नवीन कार्यों की स्वीकृति दी जायेगी।

11. प्रशासनिक व्यय से सम्बन्धित निर्देश :-

योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय की भी आवश्यकता होगी जिसके लिए योजना के वार्षिक आवंटन की 01 प्रतिशत राशि उपलब्ध होगी। प्रशासनिक व्यय हेतु प्रचलित लोक उपापन नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

प्रशासनिक व्यय में निम्नानुसार कार्य अनुमत होंगे –

1. राज्य स्तर हेतु –

- i. आईटी सिस्टम, पोर्टल के विकास एवं प्रबन्धन संबंधित कार्य।
- ii. थर्ड पार्टी मूल्यांकन।
- iii. प्रशिक्षण/कार्यशाला/आमुखीकरण/समीक्षा बैठक में होने वाले व्यय, योजना का प्रचार-प्रसार।
- iv. राज्य स्तर हेतु आवश्यक संसाधन एवं विशेषज्ञों को मानदेय।
- v. अदालती मामलों पर किये गये व्यय।
- vi. स्टेशनरी, फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, इन्टरनेट, कार्यालय फर्नीचर एवं मैन विथ मशीन।
- vii. अनुबंधित वाहनों पर व्यय। (अधिकतम राशि रु. 5 लाख वार्षिक)
- viii. अभिलेख संधारण।
- ix. कार्यों की गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु सतत् मॉनिटरिंग के कार्य।

2. जिला स्तर हेतु -

- i. इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स के चिन्हीकरण हेतु सर्वे कार्य।
- ii. वार्षिक कार्य योजना के निर्माण/इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स का चिन्हीकरण/सर्वेक्षण/डाटा संग्रहण/तकनीकी सहयोग आदि के लिए विशेषज्ञ संस्था की सेवाएं।
- iii. विकास के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर)।
- iv. कार्यों की गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु सतत् मॉनिटरिंग के कार्य।
- v. थर्ड पार्टी मूल्यांकन।
- vi. स्टेशनरी, फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, इन्टरनेट एवं मैन विथ मशीन।
- vii. अनुबंधित वाहनों पर व्यय। (अधिकतम राशि रु. 3 लाख वार्षिक)

12. जिला स्तरीय समिति :-

कार्यक्रम की क्रियान्विति एवं नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। जिसकी अध्यक्षता जिला कलक्टर करेंगे। चयनित क्षेत्र के सांसदगण, विधायक एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी (लाईन विभाग) एवं सीमा सुरक्षा बल के प्रतिनिधि इसके

सदस्य होंगे एवं संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) सदस्य सचिव रहेंगे। समिति जिला विकास वार्षिक योजना का निर्धारण, क्रियान्वयन, सम्पादन, उपलब्ध धन राशि के त्वरित उपयोग, गुणवत्ता पूर्ण परिसम्पत्तियों का सृजन एवं नियंत्रण से संबंधित समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी।

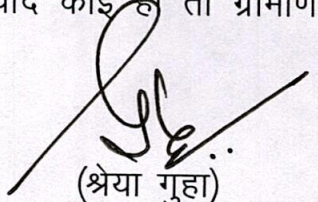
13. राज्य स्तरीय समिति :-

राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार करेंगे। समस्त लाईन डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं सीमा सुरक्षा बल के प्रतिनिधि समिति के सदस्य रहेंगे। शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे।

राज्य स्तरीय विकास समिति के उत्तरदायित्व :-

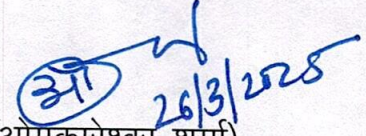
1. विभागीय ई-वर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तावों के साथ-साथ राज्य स्तर पर प्राप्त अन्य प्रस्तावों को शामिल करते हुए वरीयता क्रम में परीक्षण कर प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी।
2. समिति कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के त्वरित उपयोग एवं गुणवत्तापूर्ण परिसम्पत्तियों के सृजन करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करेगी।
3. विकास से संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा व उसमें सुधार हेतु मार्गदर्शन।
4. किसी भी कार्य के लिए उप-समितियों का गठन कर सकेगी एवं आवश्यकतानुसार किसी व्यक्ति विशेष को विशेष रूप से आमंत्रित अथवा मनोनीत भी कर सकेगी।

इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों की व्याख्या/स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो ग्रामीण विकास विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।


(श्रेया गुहा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैं :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री (वित्त), राजस्थान।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास।
6. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि।
7. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
8. निजी सचिव, महानिदेशक इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव समस्त।
10. निजी सचिव, राज्य मिशन निदेशक, राजीविका।
11. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
12. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन/जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण/एस.एस.ए.ए.टी/डीआईपीआर।
13. संभागीय आयुक्त, समस्त।
14. जिला कलक्टर, समस्त।
15. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
16. शासन उपसचिव (प्रशासन/परि. निदे. एवं पदेन उपसचिव समस्त/अधीक्षण अभियंता) ग्रावि।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रावि), जिला परिषद, समस्त को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त मार्गदर्शिका की एक-एक प्रति संबंधित माननीय संसद सदस्य/विधायक/जिला प्रमुख को उपलब्ध करावें।
18. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।


(ओमकारेश्वर शर्मा)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (SAP)